(a) whether Government have formulated a National Policy on Control of Pollution; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. Protection of the environment has always been a major concern and has been built into all programmes, projects and policies taken up so far. This has to be a continuing process. As part of the process, who have to seek integration of environmental and economic aspects in development planning: lay stress on the preventive aspects in pollution abatemen; promote technological inputs for reducing the industrial pollutants and increase reliance upon cooperation in securing a clean environment particularly the support of the State Governments. Keeping these considerations in view, a policy statement on abatement of pollution has been prepared to deal with integration of environmental and economic aspects in the development planning and stress on the preventive aspects in pollution abatement. The objective of this policy is to integrate environmental considerations into decision making at all levels. To achieve this, steps have to be taken to:

—prevent pollution at source:

—encourage, develop and apply the best available, practicable technical solutions;

—ensure that the pollutor pays for the pollution and control arragegements.

—focus protection on heavily polluted areas and river stretches; and

—involve the public in decision making.

राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य

199. श्री ईश दत्त यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों में पशु अस्पताल नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां ऐसे अस्पताल हैं तथा उन पर पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वन्यजीव संबंधी अपराध के मामले

200. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव संबंधी अपराध के राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ख) उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Private forest rearing by allotting Government Promboke Lands

201. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government propose to encourage the Private forest rearing by allotting Government Promboke lands; and

(b) whether Government have any proposal under their consideration to establish Private afforestation of waste lands ?

THE MINISTER OF STATE OF MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Governments wastelands are referred to as poromboke lands in Tamil Nadu. Allotment of lands is done at the State level by the concerned State Governments. The question of the Government of India

allotting poromboke lands for raising private forests does not, therefore, arise.

(b) Afforestation of wastelands held by private persons is being encouraged through programmes of agro-forestry and farm-forestry.

Area of Dal Lake in Kashmir

202. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what was the total area of Dal Lake in Kashmir in 1950;

(b) what is the areas at present; whether it has shrunk;

(c) whether the colour of water in Dal has changed; if so, the reasons therefor; and

(d) what steps are contemplated to set it right ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) As per available information, within the living memory, the open water area of the Dal Lake has shrunk from 24 sq. km. to 15 sq. km.

(c) and (d) In a small portion in South Eastern part of the Lake, the water colour has changed due to red scum like formation of algal bloom. The State Government of Jammu and Kashmir have sanctioned Rs. 2.00 lakhs so far to investigate the causative factors responsible for the algal bloom and the remedial measures to prevent its recurrence.

देश में जलाऊ लकड़ी की गुणवत्ता

203. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वनों में जलाऊ लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ताकि उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके ;

(ख) लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में जलाऊ लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो वैकल्पिक उपाय के लिये बतौर जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाने की योजनाओं में किन-किन राज्यों में प्रगति हो रही है तथा यह कार्य कितने-कितने क्षेत्र में हो रहा है ; और

(घ) ऐसे वृक्षों के नाम क्या-क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1987 के अनुसार, देश में जलाने की लकड़ी की अनुमानित मांग लगभग 235 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि सतत वार्षिक अनुमानित वन उत्पादन लगभग 40 मिलियन घन मीटर है ।

(ग) "क्षेत्रोन्मुख जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है इस स्कीम के तहत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये)

(घ) जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के तहत निम्नलिखित मुख्य प्रजातियां उगाई जा रही हैं:—

1. अकेशिया निलोटिका
2. प्रोसोपिस जूलीफलोरा
3. अकेशिया आरिकुलिफार्मिस
4. कैजुअरिना इक्विपसिटीफोलिया
5. यूकेलिप्टस टेरिटिकोर्निस
6. केशिया सियामिया
7. पाइनस राक्सबर्घी
8. अकेशिया केटेचु
9. ल्यूकीना ल्यूकोसिफाल।
10. करकस प्रजातियां